

फरवरी, 2017 के महत्वपूर्ण प्रयास

- * विद्युत संबंधी शिकायतों का भोपाल स्थित कॉल सेंटर द्वारा उचित निराकरण नहीं किए जाने के संबंध में प्रमुख सचिव, ऊर्जा विभाग, भोपाल, प्रबंध संचालक, म. प्र. मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कं. लि., भोपाल एवं मुख्य महाप्रबंधक, ग्वालियर रीजन एवं महाप्रबंधक, शहर वृत्त, म. प्र. मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कं. लि., ग्वालियर को पत्र प्रेषित कर माँग की गई है कि विद्युत शिकायत दर्ज कराने के लिए प्रारम्भ की गई नई सेवा को सुचारु रूप से संचालित किए जाने हेतु उचित कार्यवाही की जाए, ताकि उपभोक्ताओं को किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़े।
- * म. प्र. लघु उद्योग निगम द्वारा रॉ मटेरियल डिपो को बंद किए जाने के संबंध में प्रमुख सचिव, लघु उद्योग विभाग को पत्र लिखकर माँग की गई है कि एलयूएन, ग्वालियर द्वारा रॉ मटेरियल डिपो को बंद करने से इसका उत्पादन कर रही स्थानीय एसएसआई यूनिट्स के सामने काफी समस्याएँ उत्पन्न हो गई हैं और यह इकाईयाँ बंद होने की स्थिति में है।
- * अशासकीय विद्यालयों में शासकीय पुस्तकों से अध्ययन अनिवार्य किए जाने हेतु प्रदेश के मुख्यमंत्री, माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान, स्कूल शिक्षा मंत्री-माननीय कुँ. विजय शाह, मुख्य सचिव, म. प्र. शासन एवं प्रमुख सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, म. प्र. शासन को पत्र लिखकर तत्संबंध में निजी विद्यालयों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही करने हेतु संबंधित अधिकारियों को आदेशित करने की माँग की गई है, ताकि अशासकीय विद्यालयों में राज्य सरकार द्वारा प्रकाशित की जाने वाली पाठ्य पुस्तकों से अध्ययन सुनिश्चित हो सके।
- * केन्द्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री-श्री अनन्त कुमार, केन्द्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री, भारत सरकार-श्री नरेन्द्र सिंह तोमर एवं सचिव, केन्द्रीय उर्वरक/खाद विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली को पत्र लिखकर केन्द्रीय उर्वरक मंत्रालय द्वारा म. प्र. के लिए स्वीकृत खाद कारखाने की स्थापना ग्वालियर में किए जाने की माँग की गई है।
- * 18वें इण्ड-एक्सपो के सफलतम आयोजन के लिए हार्दिक आभार व धन्यवाद व्यक्त करते हुए केन्द्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम मंत्री, भारत सरकार-माननीय श्री कलराज मिश्र एवं राज्यमंत्री-माननीय श्री गिरिराज सिंह एवं केन्द्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री, भारत सरकार-माननीय श्री नरेन्द्र सिंह तोमर को पत्र प्रेषित किए गए।
- * केन्द्रीय रेल राज्यमंत्री, माननीय श्री मनोज सिन्हा एवं महाप्रबंधक, उत्तर मध्य रेलवे, इलाहाबाद को पत्र प्रेषित कर बेंगलोर राजधानी एक्सप्रेस (22692/22691) का स्टॉपेज शीघ्र ही ग्वालियर में किए जाने की माँग की गई है। पत्र में केन्द्रीय रेल राज्यमंत्री, माननीय श्री मनोज सिन्हा द्वारा गत वर्ष दिनांक 27 फरवरी को चेम्बर भवन में पधारने के अवसर पर इस ट्रेन का स्टॉपेज ग्वालियर में दिए जाने के आश्वासन का भी उल्लेख किया गया है। पत्र में कहा गया है कि माननीय रेल राज्य मंत्री द्वारा ग्वालियरवासियों को दिए गए आश्वासन के बावजूद भी आज दिनांक तक तत्संबंध में रेलवे बोर्ड द्वारा कोई उचित कार्यवाही नहीं किए जाने से ग्वालियरवासी काफी निराश है। रेलवे बोर्ड द्वारा 23 जुलाई, 16 से इस ट्रेन का स्टॉपेज आगरा कैंट में स्वीकृत कर दिया गया है, जबकि उक्त ट्रेन पूर्व से ही झाँसी में रुकती आ रही है। यानि कि उक्त ट्रेन के उत्तरप्रदेश में दो स्टॉपेज हो गए हैं, जबकि मध्यप्रदेश में केवल भोपाल स्टेशन पर ही इस ट्रेन का स्टॉपेज है। अतः ग्वालियर अंचल के उद्योगपतियों, व्यवसाईयों सहित आम यात्रियों की बहुप्रतीक्षित उपरोक्त माँग को ध्यान में रखते हुए, उक्त ट्रेन का ग्वालियर स्टेशन पर स्टॉपेज, शीघ्रातिशीघ्र सुनिश्चित कराने हेतु एक प्रस्ताव रेलवे बोर्ड की ओर प्रेषित किया जाए, ताकि ग्वालियरवासियों को इस ट्रेन की सुविधा उपलब्ध हो सके।
- * विधायक, श्री भारत कुशवाह जी को पत्र प्रेषित कर जौरासी हनुमान मंदिर मार्ग का सुदृढीकरण किए जाने की माँग की गई है, ताकि मंदिर पर दर्शनार्थ आने वाले हजारों भक्तगणों को आवागमन में सुविधा हो सके।

* मण्डल रेल प्रबंधक, उत्तर मध्य रेलवे, झाँसी को पत्र प्रेषित कर, ग्वालियर स्थित फूलबाग रेलवे क्रॉसिंग पर ऑटोमेटिक गेट लगाए जाने की माँग की गई है, ताकि इस रेलवे क्रॉसिंग पर प्रतिदिन होने वाले ट्रेफिक जाम से स्थानीय नागरिकों को राहत मिल सके ।

* मण्डल रेल प्रबंधक, उत्तर मध्य रेलवे, झाँसी को पत्र प्रेषित कर, भिण्ड-कोटा (59822/59821) ट्रेन में ए. सी. कोच लगाए जाने की माँग की गई है, ताकि ग्वालियर अंचल के रेल यात्रियों को होने वाली परेशानी से राहत मिल सके।

* नगरीय विकास एवं आवास मंत्री, माननीया श्रीमती मायासिंह एवं सचिव, नगरीय विकास एवं आयुक्त नगरीय विकास व पर्यावरण विभाग, म. प्र. शासन को पत्र प्रेषित कर, नगर-निगम, ग्वालियर द्वारा निगम सीमा में आने वाले क्षेत्रों में नगरीय यातायात प्रबंधन फण्ड का आरोपण वर्ष सितम्बर, 2011 से किए जाने पर ध्यान आकर्षित करते हुए उल्लेख किया गया है कि इस प्रकार का कर प्रदेश में ग्वालियर को छोड़कर कहीं पर भी लागू नहीं है । अतः पत्र में माँग की गई है कि उपरोक्त कर को समाप्त करने हेतु आवश्यक एवं उचित कार्यवाही की जाए, ताकि इस शुल्क से राहत मिल सके।

* भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के चेयरमैन को पत्र प्रेषित कर, ग्वालियर-झाँसी राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक-75 के 4-लेन निर्माण कार्य की प्रगति हेतु एनएचएआई द्वारा अभी तक की गई कार्यवाही एवं इस प्रोजेक्ट के पूर्ण होने की क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है । इससे अवगत कराने की माँग पत्र के माध्यम से की गई है ।

* केन्द्रीय नागर विमानन राज्यमंत्री-श्री जयंत सिन्हा को पत्र प्रेषित कर, बँगलोर-पुणे-ग्वालियर/ग्वालियर-पुणे-बँगलोर के मध्य सप्ताह में कम-से-कम दो दिन (शनिवार एवं रविवार) को हवाई सेवा उपलब्ध कराए जाने की माँग की गई है ।

* लोकसभा अध्यक्ष, माननीया श्रीमती सुमित्रा महाजन (ताई) एवं चेयरमैन, रेलवे बोर्ड, नई दिल्ली को पत्र प्रेषित कर, डबल डेकर ट्रेन नं. डबल डेकर ट्रेन नं. 22185/22186 का संचालन ग्वालियर-इन्दौर-ग्वालियर के मध्य इंटरसिटी के रूप में प्रतिदिन किए जाने की माँग की गई है क्योंकि ग्वालियर-इन्दौर के मध्य एकमात्र नियमित ट्रेन का संचालन रात्रि के समय रेलवे द्वारा किया जा रहा है और इस ट्रेन की स्थिति यह है कि अधिकांश यात्रियों को, टिकट कन्फर्म न होने के कारण अपनी यात्रा निरस्त करनी पड़ती है । अतएव ग्वालियर एवं इंदौर के नागरिकों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, उपरोक्त डबल डेकर इंटरसिटी ट्रेन का संचालन सुनिश्चित कराने की माँग की गई है, ताकि इसके संचालन से दोनों ऐतिहासिक शहरों के उद्योगपति व व्यवसाई सहित आमनागरिक लाभांविता हो सकें ।

* प्रबंध संचालक, म. प्र. स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कार्पोरेशन लि., भोपाल को पत्र प्रेषित कर, जानकारी चाही गई है कि केन्द्र सरकार द्वारा ग्वालियर के लिए प्रस्तावित इलेक्ट्रॉनिक क्लस्टर की मंजूरी कब तक केन्द्र सरकार से मिलने की संभावना है और इसकी स्थापना कब तक ग्वालियर में हो जाएगी ।

* म. प्र. में पेट्रोल एवं डीजल पर सर्वाधिक करारोपण के साथ-साथ पेट्रोल पर रु. 4/- प्रति लीटर अतिरिक्त कर वसूल किए जाने के विरुद्ध चेम्बर द्वारा प्रदेश के मुख्यमंत्री, श्री शिवराज सिंह चौहान एवं वित्त एवं वाणिज्यिक कर मंत्री-श्री जयंत मलैया को पत्र प्रेषित कर, माँग की गई है कि प्रदेश सरकार द्वारा इसी बजट में पेट्रोल एवं डीजल पर वैट की दरें पड़ौसी राज्य, उत्तरप्रदेश व राजस्थान के अनुरूप करने की घोषणा की जाए । साथ ही, पेट्रोल पर हाल ही में लगाए गए अतिरिक्त कर को भी समाप्त किया जाए क्योंकि जीएसटी में पेट्रोल एवं डीजल को बाहर रखा गया है और देश में जीएसटी लागू होने पर भी इन पेट्रोलियम उत्पादों पर कर की दरें तय करने का अधिकार प्रदेश सरकार के पास ही रहेगा ।

* मालनपुर में संचालित परिवहन विभाग के चेक पोस्ट के कारण मुख्य मार्ग पर यातायात जाम की स्थिति बनी रहने एवं ट्रांसपोर्ट्स द्वारा स्थानीय उद्योगपतियों से मालनपुर के लिए ट्रक बुकिंग के समय रुपये तीन हजार की अतिरिक्त माँग किए जाने की समस्या सहित आए दिन स्थानीय समाचार-पत्रों में आरटीओ चेक पोस्ट, मालनपुर पर तैनात परिवहन कर्मचारियों द्वारा ट्रकों से की जा रही अवैध वसूली के संबंध में परिवहन आयुक्त, ग्वालियर एवं प्रमुख सचिव, परिवहन विभाग, भोपाल को पत्र लिखकर, उक्त आरटीओ चेक पोस्ट को प्रदेश की सीमा 'फूफ' में स्थापित कर संचालित किए जाने की माँग की गई है। साथ ही, मालनपुर चेक पोस्ट पर जारी अवैध वसूली को सख्ती से रोके जाने तथा इसे कम्प्यूटराइज्ड कर, ऑनलाईन किए जाने की भी माँग की गई है।

* जिलाधीश एवं अध्यक्ष जिला मूल्यांकन समिति को पत्र प्रेषित कर, कलेक्टर गाइड लाइन में जमीन एवं कंस्ट्रक्टेड एरिया दोनों पर 20% तक कमी करते हुए आगामी वर्ष के लिए कलेक्टर गाइडलाइन निर्धारित किए जाने की माँग की गई है, ताकि प्रॉपर्टी के दामों में चल रही मंदी के दौर से निपटने में सहायता मिल सके।

* चेयरमैन, रेलवे बोर्ड, नई दिल्ली को पत्र लिखकर शताब्दी एक्सप्रेस (12002/12001) के कोच में ब्रेक लगने के समय यात्रियों को एकदम झटका लगने तथा उक्त ट्रेन में यात्रा के दौरान यात्रियों लगने वाले झटके की समस्या को प्राथमिकता के आधार पर ठीक कराने की माँग की गई है, ताकि यात्रियों को होने वाली परेशानियों से राहत मिल सके।

* केन्द्रीय रेल राज्यमंत्री, श्री मनोज सिन्हा को पुनः पत्र प्रेषित कर बँगलोर राजधानी एक्सप्रेस का स्टॉपेज शीघ्र ही ग्वालियर में किए जाने की माँग की गई है।

* चेयरमैन, रेलवे बोर्ड, नई दिल्ली को पत्र लिखकर शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन में भोजन व्यवस्था को टिकिट बुकिंग के समय ऐच्छिक (ऑप्शनल) आधार पर करने की माँग की गई है, ताकि यात्रीगण अपनी सुविधानुसार विकल्प का चयन कर सकें।

* डीआरएम, झाँसी को पत्र लिखकर सुझाव दिया गया है कि ग्वालियर रेलवे स्टेशन पर प्रीमियम पार्किंग में केवल एक से डेढ़ घंटे तक ही कार खड़ी करने की अनुमति दी जाए और इससे अधिक समय तक कार पार्क करने वालों को सामान्य पार्किंग में वाहन खड़े करने के लिए प्रेरित किया जाए व व्यवस्था की जाए। साथ ही, प्रीमियम पार्किंग की दरें भी कम की जाएँ क्योंकि रेलवे का उद्देश्य पार्किंग से पैसा कमाना नहीं है।
